

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3172

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ

3172. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दौसा सहित राजस्थान और पूरे देश में पिछले दस वर्षों में स्वीकृत ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें वर्तमान में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार संख्या कितनी है और स्थिति क्या है तथा तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए पिछले दस वर्षों के दौरान बोलियाँ आमंत्रित की गईं और प्राप्त हुईं, लेकिन निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन विलंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, इनकी लागत में वृद्धि को रोकने और इनके काम में तीव्रता लाने के लिए कोई विशिष्ट नीति या सुधारात्मक उपाय कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार दौसा सहित राजस्थान में सभी लंबित या अभी तक शुरू नहीं हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पुनः शुरू करने और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) समापन के लिए विचाराधीन/समापन समय से पहले बंद होने वाले परियोजनाओं को छोड़कर, 643 निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएँ, जिन्हें मंजूरी दी गई और तत्पश्चात वित्त वर्ष 2014-15 से सौंपा गया है और जिनकी कुल लागत लगभग 4.13 करोड़ रुपये है, परियोजना को पूरा करने के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना और अनुबंध के अनुसार अपनी मूल निर्धारित समापन तिथि को पार कर चुकी हैं। विलंबित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न किया गया है।

(ग) लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाले 158 एनएच परियोजनाएँ सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अपेक्षित शर्तों के पूरा होने के साथ-साथ वित्तीय समापन हासिल करने और बैंक की जमानत जमा करने के लिए संविदाकार/रियायतग्राही के पास मौजूद समय को छोड़कर, बिना ऋण मुक्त वाली भूमि की उपलब्धता और वन और वन्यजीव मंजूरी सहित अन्य अनुमतियों की पूर्ति विलंबित होने के कारण नियत तिथि घोषित नहीं की जा सकी।

(घ) और (ङ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/कठिनाईयों की समीक्षा और समाधान के परितंत्र का लाभ उठाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अलावा, सरकार आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन की प्राप्ति में तेजी लाने और नई परियोजनाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के लिए पूरी प्रयास कर रही है।

अनुलग्नक

“राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ” के संबंध में श्री मुरारी लाल मीना के द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3172 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल	
	सं.	लागत
अंडमान और निकोबार	5	1463
आंध्र प्रदेश	38	19947
अरुणाचल प्रदेश	13	3857
असम	24	9750
बिहार	33	28183
छत्तीसगढ़	13	4788
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	102
दिल्ली	1	1467
गोवा	5	151
गुजरात	17	18539
हरियाणा	10	12871
हिमाचल प्रदेश	14	7346
जम्मू और कश्मीर	30	26017
झारखंड	18	13281
कर्नाटक	49	26738
केरल	13	39161
लद्दाख	4	1265
मध्य प्रदेश	25	9183
महाराष्ट्र	66	45120
मणिपुर	21	7071
मेघालय	4	1120
मिजोरम	7	2158
नागालैंड	11	3404
ओडिशा	28	7616
पंजाब	22	22527
राजस्थान	17	5561
सिक्किम	9	3323
तमिलनाडु	21	21252
तेलंगाना	28	15967
त्रिपुरा	5	986
उत्तर प्रदेश	48	37035
उत्तराखंड	30	11442
पश्चिम बंगाल	13	4372
कुल	643	413064

\*\*\*\*\*